पश्चिम बंगाल की राजनीति

SPECT
RESEARCH ASSOCIATION

SPECT Foundation

SPECT
RESEARCH ASSOCIATION

SPECT Foundation

एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिये कि

27% मुसलमान और 23.51% दलित सबसे मजबूत कड़ी हैं।

चाहे बंगाल की राजनीति पर हमेशा कंट्रोल अपर कास्ट का रहा है मगर उन्होंने हमेशा इन दोनों समुदाय को साध कर ही प्रदेश की सत्ता को अपने कण्ट्रोल में रखा है।

पश्चिम बंगाल की कुल आबादी का 27% मुस्लिम

इसके बावजूद आज तक मुसलमानों को आबादी के हिसाब से विधानसभा में राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली है। आबादी के हिसाब से विधानसभा में 79 मुस्लिम विधायक होने चाहिए मगर 2021 के विधानसभा में केवल 42 मुस्लिम विधायक चुने गए थे।

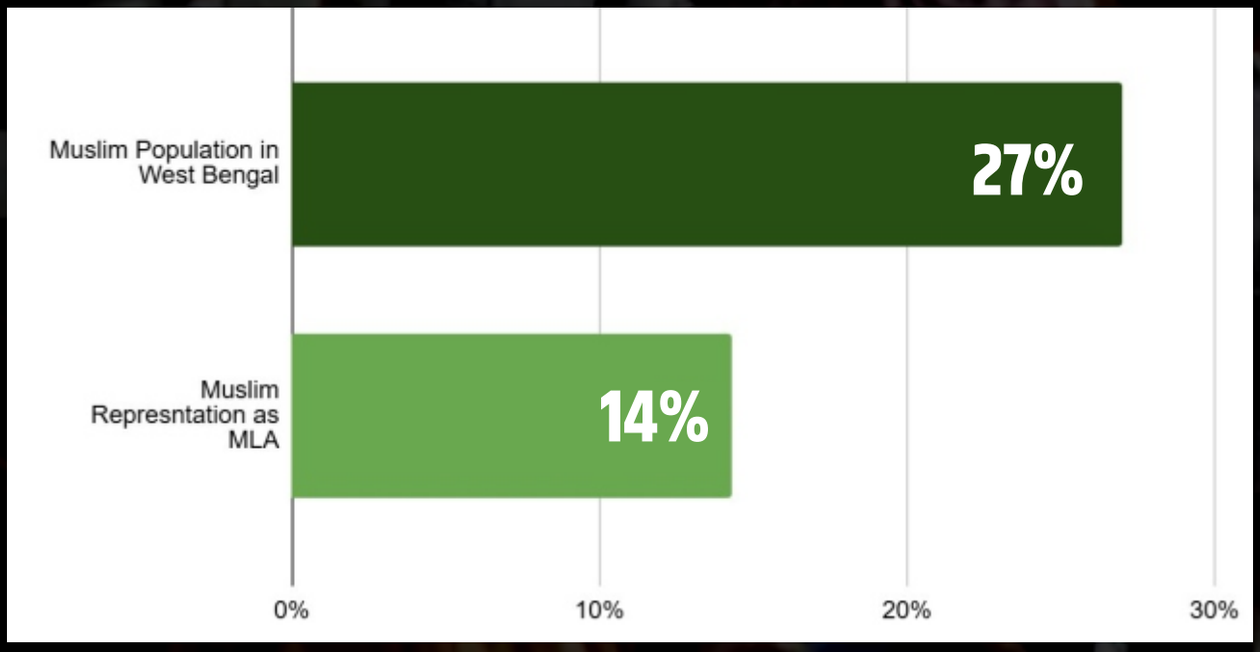

SPECT RESEARCH ASSOCIATION | SPECT Foundation

पश्चिम बंगाल में 66 सीटें दलित समुदाय के लिए आरक्षित

जो SC वोट कुछ समय पहले तक TMC के साथ होते थे उन्होंने अब विकल्प के रूप में भाजपा को भी चुनना शुरू कर दिया है। भाजपा का अधिक प्रभाव भी उत्तर बंगाल में ही है जिसका नतीजा ये था कि 2021 के विधानसभा में 66 SC आरक्षित सीटों में से 29 पर भाजपा की जीत हुयी थी।

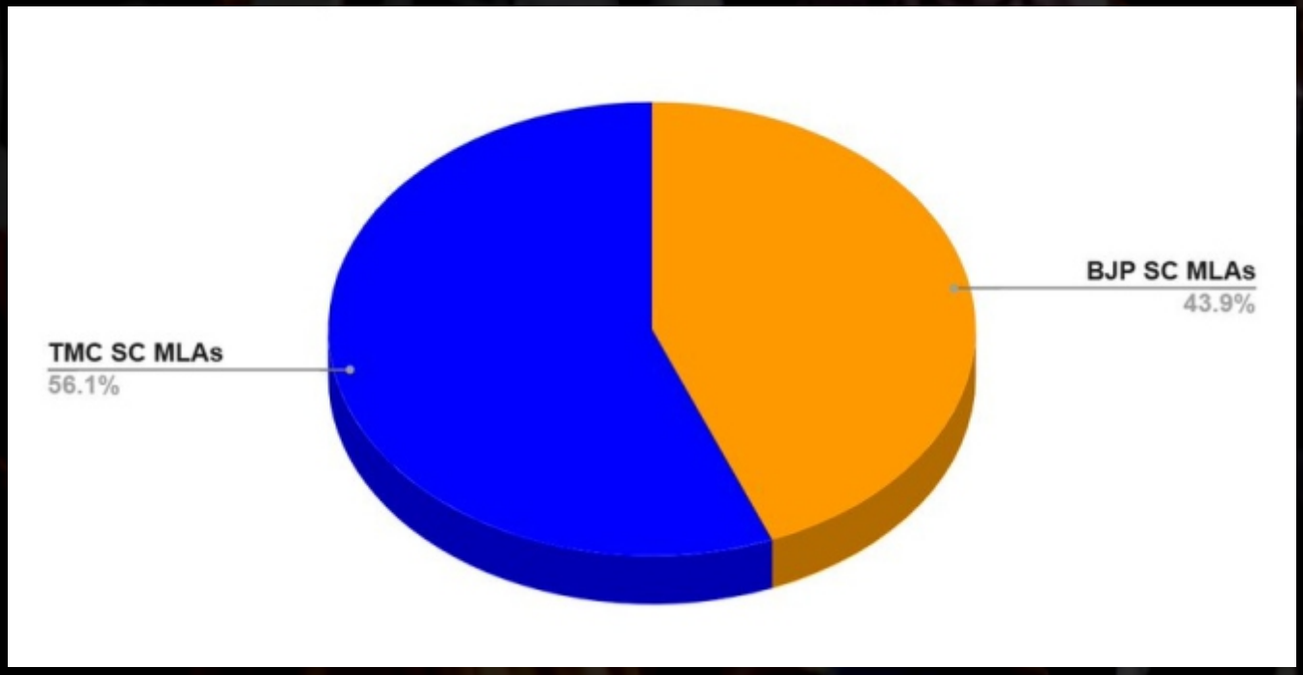

SPECT RESEARCH ASSOCIATION | SPECT Foundation

पश्चिम बंगाल की विधानसभा में 66 सीटें दलित समुदाय के लिए आरक्षित हैं। इनको अगर गहरायी से आंकड़ों की नज़र से देखेंगे तो समझ में आयेगा कि इनमें से **कई सीटों पर दलित आबादी कम और मुस्लिम आबादी ज्यादा होने के बावजूद इनको आरक्षित किया गया है**।

इनमें से **3 सीटें पूरी तरीके से मुस्लिम बहुल हैं** जहां मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है इसके बावजूद वहां से परिसीमन की वजह से मुस्लिम चुनाव ही नहीं लड़ सकता है। **इसमें नबग्राम, मीनाखान और खारग्राम सीट शामिल हैं।**

ऐसे ही **3 सीटें ऐसी** है जहां **मुस्लिम मतदाता 44 फीसदी से ज्यादा** है **बावजूद इसके उन सीटों को आरक्षित कर दिया गया है**। इसमें **मगरहाट पुरबा, हेमताबाद और स्वरूपनगर** की सीट शामिल है।

Assembly Name	Loksabha	Muslims %	Dalit %	Reserved
Nabagram	Jangipur	53.20%	23.60%	SC
Minakhan	Basirhat	52.20%	29.09%	SC
Khargram	Jangipur	50.30%	22.06%	SC
Magrahat Purba	Jaynagar (SC)	44.90%	34.61%	SC
Hemtabad	Raiganj	44.30%	35.21%	SC
Swarupnagar	Bangaon (SC)	44.10%	29.64%	SC

अक्सर लोगों को इस बात का भ्रम रहता है कि अगर मुस्लिम बहुल दलित आरक्षित सीटों की कोई बात करता है तो वो आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहा है मगर हकीकत में मामला तो उल्टा है।

जिस दलित आरक्षण का प्रावधान हाशिये पर धकेले गए एक समाज को मुख्यधारा में लाने और राजनीतिक रूप से सशक्त करने के लिए किया गया था उसका इस्तेमाल परिसीमन में दलित बहुल सीटों को अनारक्षित छोड़ कर कुठाराघात करने का प्रयास जारी है।

आप खुद ही बताईये कि आखिर क्यों पश्चिम बंगाल की 5 दलित बहुल सीटों को आरक्षित करने की जगह जनरल श्रेणी में छोड़ दिया गया है। इनमें से एक सीट **हबीबपुर को केवल 27% आदिवासी आबादी होने के बावजूद ST के लिए आरक्षित कर दिया गया** है जबकि इस सीट पर दलित आबादी लगभग 50 फीसदी के करीब है।

Assembly Name	Loksabha	Dalit %	Muslim%	Category
Habibpur (ST)	Maldaha Uttar	48.97%	6%	ST (27.18%)
Tufanganj	Alipurduars (ST)	47.87%	18.70%	General
Alipurduar	Alipurduars (ST)	42.84%	5.30%	General
Natabari	Cooch Behar (SC)	41.97%	24.80%	General
Dinhata	Cooch Behar (SC)	41.42%	31.60%	General

परिसीमन के मामले में बहुत सारे झोल है जो इसकी निष्पक्षता पर सवाल उत्पन करते है। सवाल तो ये है कि क्या दलित अथवा आदिवासी समाज के लिए सीटें आरक्षित करने का कोई फिक्स पैमाना है जिसकी बुनियाद पर ये सब किया जाता है?

शायद नहीं! सब मन मर्जी मुताबिक चल रहा है। उदहारण के साथ समझने की कोशिश करते है।

पैमाना: दलित आबादी का अधिक होना!

एक तरफ परिसीमन में 42.7% दलित आबादी वाली बनगांव लोकसभा की सभी सात विधानसभा सीटों को SC के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इसमें अधिकतर सीटें उत्तर 24 परगना की सीटें हैं जहां दलित आबादी केवल 20% है। जिसमें 44.1% मुस्लिम आबादी वाली स्वरूपनगर सीट को भी आरक्षित कर दिया गया है।

Assembly Name	Loksabha	Muslims %	Dalit %	Reserved
Swarupnagar	Bangaon (SC)	44.10%	29.64%	SC
Haringhata	Bangaon (SC)	21.70%	39.11%	SC
Bangaon Uttar	Bangaon (SC)	13.90%	39.41%	SC
Bagda	Bangaon (SC)	12.60%	53.14%	SC
Bongaon Dakshin	Bangaon (SC)	8.10%	49.57%	SC
Gaighata	Bangaon (SC)	7.40%	43.81%	SC
Kalyani	Bangaon (SC)	6.70%	42.72%	SC

वहीं दूसरी तरफ भारत का एकलौता जिला **कूच बिहार जो दलित बहुल है उस लोकसभा की 7 विधानसभा सीटों में से केवल 4 सीटों को ही आरक्षित किया गया** है। जबकि इस लोकसभा में दलित आबादी 48.6% है। सोचिये दलित बहुल नटबारी और दिनहाटा को जनरल श्रेणी में ही रहने दिया गया है।

Assembly Name	Loksabha	Muslims %	Dalit %	Reserved
Sitai	Cooch Behar (SC)	38.10%	50.56%	SC
Sitalkuchi	Cooch Behar (SC)	26.10%	63.59%	SC
Cooch Behar Uttar	Cooch Behar (SC)	17.70%	44.97%	SC
Mathabhanga	Cooch Behar (SC)	15.20%	59.74%	SC
Natabari	Cooch Behar (SC)	24.80%	41.97%	General
Dinhata	Cooch Behar (SC)	31.60%	41.42%	General
Cooch Behar Dakshin	Cooch Behar (SC)	29.10%	36.19%	General

क्या मुस्लिम की परम्परागत सीटों को भी आरक्षित किया जायेगा!

सबसे बड़ा सवाल तो यही उभर कर सामने आता है कि अगर 2009 के परिसीमन में जंगीपुर लोकसभा की नबग्राम और खारग्राम मुस्लिम बहुल होने के बावजूद आरक्षित कर दी गयी थी तो **क्या गारंटी है कि जंगीपुर लोकसभा की ही मुस्लिम बहुल और मुस्लिम विधायका वाली रघुनाथगंज और लालगोला को परिसीमन में आरक्षित नहीं किया जायेगा?**

ऐसे ही बसीरहाट लोकसभा की मुस्लिम बहुल मीनाखान को आरक्षित कर दिया है तो क्या इस बात का यकीन रहेगा कि आगामी परिसीमन में बसीरहाट लोकसभा की ही हरोआ को मुस्लिम बहुल सीट और मुस्लिम विधायक वाली सीट होने के बावजूद आरक्षित नहीं किया जायेगा?

SPECT RESEARCH ASSOCIATION | SPECT Foundation

इससे भी आगे बढ़ कर जैसे जयनगर (SC) लोकसभा की मगराहट पुरबा और जयनगर को मुस्लिम केंद्रित होने के बावजूद आरक्षित कर दिया गया है तो **आगामी 2026 के परिसीमन में इसी लोकसभा की मुस्लिम विधायक वाली कैनिंग पुरबा सीट को आरक्षित नहीं किया जा सकता है।**

Muslim Majority Reserved Seats		*Muslim Majority Unreserved Seats*	
Assembly Name	**Loksabha**	**Assembly Name**	**Loksabha**
Nabagram	Jangipur	Raghunathganj	Jangipur
Khargram	Jangipur	Lalgola	Jangipur
Minakhan	Basirhat	Haroa	Basirhat
Magrahat Purba	Jaynagar (SC)	Canning Purba	Jaynagar (SC)
Jaynagar	Jaynagar (SC)		

अगर आपको लगता है मुसलमानों के साथ परिसीमन के नांम पर ये अन्याय केवल विधानसभा सीटों तक ही सीमित है तो शायद आप गलत है। **लोकसभा सीटों के परिसीमन में भी मुस्लिम सांसदी को एक सीट से ऐसा ख़त्म किया है कि दुबारा मुसलमान सांसद ही न बन पाए।**

पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के तहत एक लोकसभा सीट आती थी कटवा जिसको **2009 के परिसीमन में ख़त्म कर के दो सीटों बर्धमान पुरबा (SC) और बर्धमान दुर्गापुर में तब्दील कर दिया गया** है।

ज्ञात रहे परिसीमन से पहले इस सीट पर 10 बार मुस्लिम सांसद रहा है। **1980 से ही सीपीएम के टिकट पर सैफुद्दीन चौधरी और महबूब ज़ाहेदी 4-4 बार लगातार सांसद चुने जाते रहे हैं।**

मगर अब इन दोनों सीटों पर मुसलमानों की आबादी कम होने की वजह से कभी मुस्लिम सांसद नहीं बन पायेगा। **बर्धमान पुरबा (SC) में मुस्लिम आबादी अब 22% और बर्धमान दुर्गापुर 18% तक सीमित हो चुकी है। जो चुनावी तौर पर केवल मुस्लिम वोट के सहारे जीतने की संभावना को ख़त्म कर देता है।**

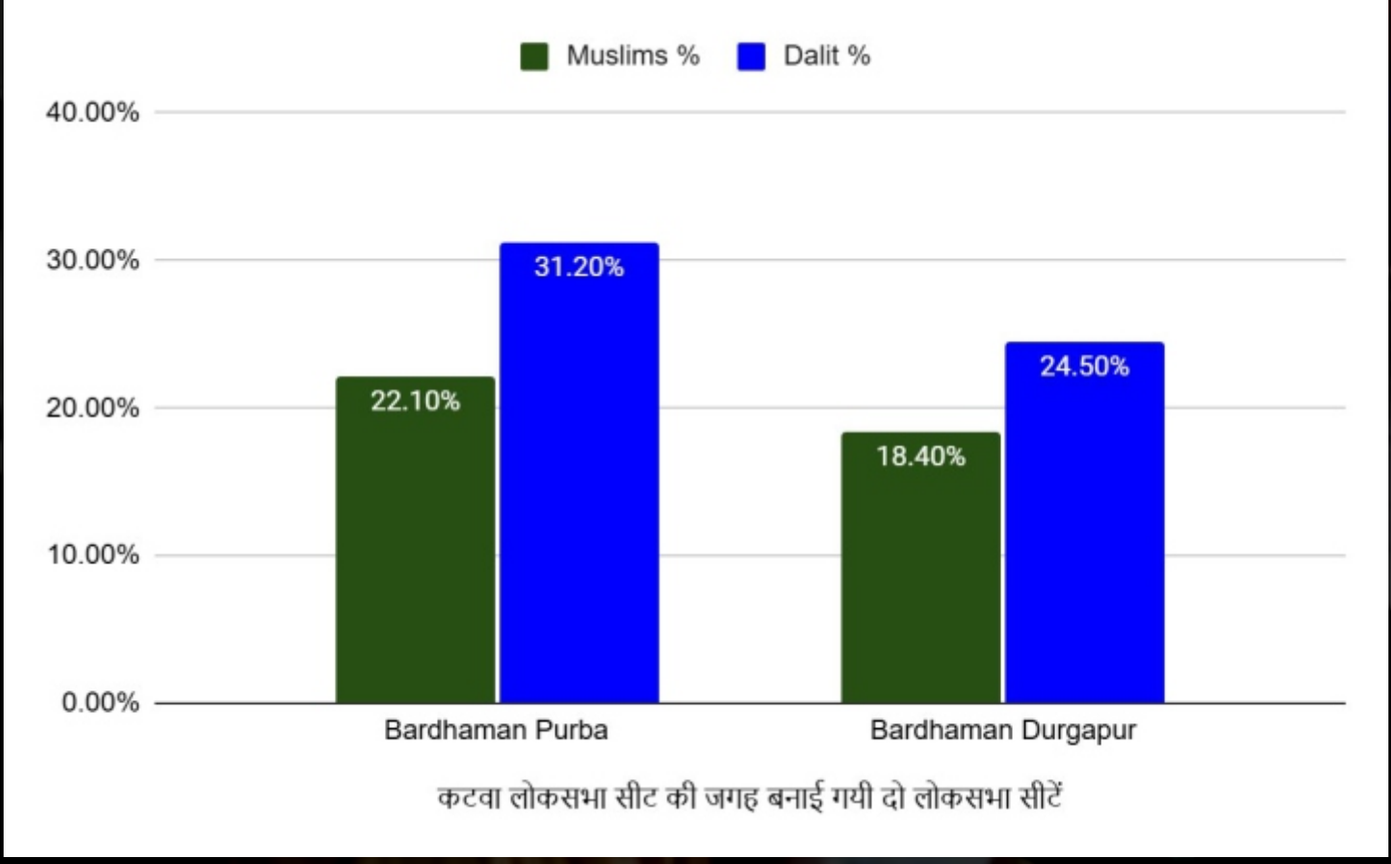

कटवा लोकसभा सीट की जगह बनाई गयी दो लोकसभा सीटें

SPECT RESEARCH ASSOCIATION | SPECT Foundation

परिसीमन की इस पूरी बहस का निष्कर्ष क्या है?

इस पूरे परिसीमन के मामले को पश्चिम बंगाल के परिदृश्य में देखने के बाद एक बात तो स्पष्ट समझ में आती है कि SC समुदाय के लिए आबादी के अनुरूप जो सीटों को आरक्षित किया जाता है उससे न ही पूरे तरीके से दलित समाज का राजनीतिक उत्थान हो पा रहा है और **न ही मुस्लिम समाज की केंद्रित सीटों के आरक्षित होने की वजह से उनकी विधानसभा में उस सीट से नुमाइंदगी हो रही है।**

दलित बहुल सीटों को छोड़ कर कम दलित आबादी वाली मुस्लिम केंद्रित सीटों को आरक्षित करने से किसका फायदा हो रहा है। **अगर 2009 का परिसीमन जो कथित तौर पर एक सेकुलर सरकार UPA के दौर में होने के बावजूद इतना अन्यायपूर्ण रहा है तो कट्टर हिंदुत्व की राजनीती करने वाली भाजपा के समय में 2026 में ये निष्पक्ष होगा ऐसा सोचना भी अपने आप में बेमानी बात होगी।**

SPECT RESEARCH ASSOCIATION | SPECT Foundation

सबसे आखिरी बात जो मुस्लिम नेता मुस्लिम बहुल सीटों से चुनाव जीत विधायक और सांसद बने घूम रहे हैं वो याद रखें कि भाजपा ने अपने दौर में असम और जम्मू कश्मीर के परिसीमन से एक बात स्पष्ट कर दी है कि **वो आगामी परिसीमन अपनी राजनीति को ध्यान में रख कर ही करेगी जिसमें मुस्लिम राजनीति का बंटाधार होना तय है।**

जिस असम में धुबरी और बरपेटा दोनों मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटें होती थी उनको ऐसा परिसीमन में बांटा गया है कि **अब दुबारा बरपेटा से मुस्लिम सांसद नहीं चुना जा सकता है।**

SPECT
RESEARCH ASSOCIATION

SPECT Foundation